

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा**  
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 74/2018 अपील

श्री भारत सिंह पिता प्रेमसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार  
महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा  
कोटडी जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेण्ट

**अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार कोटडी प्रकरण सं. 110/2018**  
**दिनांक 19.07.2018 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम**

उपस्थित –

1. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोंडेण्ट की ओर से

**निर्णय**

दिनांक 24.06.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार कोटडी प्रकरण सं0 110/2018 दिनांक 19.07.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का नंदराय की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नंदराय की सरकारी भूमि आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलार्थी के अतिक्रमण कर लेने से धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद दिनांक 10.04.2018 की पेशी पर यह लिख दिया गया कि अतिक्रमी बावजूद तामील अनुपस्थित है, जबकि अपीलार्थी को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 19.07.2018 को अपीलार्थी के विरुद्ध एक तरफा निर्णय पारित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास एवं 150/-रुपये शास्ति से दण्डित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया है, वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं, क्योंकि पूर्व में कभी भी अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया गया था। आराजी सं. 4983 के पास ही मुझ अपीलार्थी की भूमि स्थित हैं, जिससे उक्त भूमि के कुछ भाग पर मुझ अपीलार्थी का कब्जा हो गया था, किन्तु जानकारी में आते ही अपीलार्थी ने उक्त आराजी नं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया है और वर्तमान में भी उस पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और



अपीलार्थी के विरुद्ध पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2001 पेज नं. 475 पेश किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत तामील नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 19.07.2018 को अपीलार्थी के विरुद्ध एक तरफा निर्णय पारित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास एवं 150/-रूपये शास्ति से दण्डित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया है, वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं। आराजी सं. 4983 के पास ही मुझ अपीलार्थी की भूमि स्थित है, जिससे उक्त भूमि के कुछ भाग पर मुझ अपीलार्थी का कब्जा हो गया था, किन्तु जानकारी में आते ही अपीलार्थी ने उक्त आराजी नं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया है और वर्तमान में भी उस पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और अपीलार्थी के विरुद्ध पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का नन्दराय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम नन्दराय तहसील कोटडी की आराजी नं0 4983 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर संवत् 2073 में भी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार कोटडी में दर्ज कराया गया एवं उक्त न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिये। अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में प्रकरण सं. 231/2017 निर्णय दिनांक 24.04.2017 में जिस आराजी पर अपीलार्थी को बेदखल किया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उस आदेश/निर्णय व बेदखली पर्चा की प्रमाणित प्रति



रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवार हल्का नंदराय की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 से कब्जा छोड़ दिया है व अब कोई कब्जा नहीं है, न भविष्य में करेंगे। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में तहसीलदार कोटडी स्वयं अतिक्रमणसुदा भूमि का मौका निरीक्षण कर यह सत्यापन करे कि अतिक्रमी भारत सिंह पिता प्रेमसिंह महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी द्वारा ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा अतिक्रमणसुदा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया है या नहीं। यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा माफ की जाना न्योयोचित है और अधीनस्थ न्यायालय का अन्य आदेश यथावत रहने योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण सं. 110/2018 को तहसीलदार कोटडी को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार कोटडी के प्रकरण सं. 110/2018 निर्णय दिनांक 19.07.2018 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार कोटडी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण सं. 110/2018 में अतिक्रमी भारत सिंह पिता प्रेमसिंह महाजन निवासी नन्दराय तहसील कोटडी द्वारा ग्राम नंदराय तहसील कोटडी की आराजी सं. 4983 रकबा 2.00 बीघा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया है या नहीं उसका सत्यापन स्वयं करें। यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है व अन्य आदेश यथावत रहेंगे। यदि अतिक्रमण हटाया जाना प्रमाणित नहीं होता है तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 110/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2018 यथावत रहेंगे। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
भिलवाड़ा (राज.)